रिवीजनल सिविल

समक्ष पी. एस. पट्टार, न्यायमूर्ति

रामावतार,-वादी-याचिकाकर्ता।

बनाम

बालबीर और अन्य,-प्रतिवादी-उत्तरदाता।

1973 का सिविल संशोधन 168

15 जुलाई, 1975।

सिविल प्रक्रिया संहिता (5 of 1908)- आदेश 32 नियम 3 और 12-एक वाद मित्र द्वारा वाद जिसमें वादी को प्रामाणिक गलती के माध्यम से नाबालिग बताया गया है-वादी वास्तव में वाद की स्थापना की तारीख को एक मेजर है-शिकायत-क्या संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी वादी के नाम पर उसे नाबालिग बताते हुए एक अन्य व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया गया है, जो एक प्रामाणिक गलती से उसके वाद मित्र के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि वास्तव में वह वाद की स्थापना के समय बड़ा था, तो वाद को तकनीकी याचिका पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादी वाद की स्थापना की तारीख पर बड़ा था और वादी को संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वादी को अपने नाम पर वाद के साथ आगे बढ़ने और वाद मित्र को निर्वहन करने की अनुमति दी जा सके।

(पैरा 9 और 10)

सब जज प्रथम श्रेणी, नारनौल, दिनांक 1 जनवरी, 1973 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए धारा 115 सीपीसी के तहत याचिका, जिसमें कहा गया था कि मुकदमा शुरू होने की तिथि पर वादी नाबालिग नहीं था और अभिभावक के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था और वादपत्र में संशोधन।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरि मित्तल।

उत्तरदाताओं के लिए - कोई नहीं।

पट्टार, न्यायमूर्ति:-

(1)-यह राम अवतार वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन एक पुनरीक्षण याचिका है, जो अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, नारनौल के दिनांक 1 जनवरी, 1973 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके

द्वारा उसने निर्णय लिया कि वादी वाद की स्थापना के समय एक वयस्क था और उसने वाद के संशोधन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

(2) इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राम अवतार याचिकाकर्ता शिकायत के शीर्षक में पूरी तरह से वर्णित 7 कनाल 16 मरला की भूमि का मालिक है और गाँव दोहर कलां, तहसील नारनौल, जिला महिंदरगढ़ के क्षेत्र में स्थित है। यह जमीन 290 रुपये की राशि के लिए बलबीर और अन्य लोगों के साथ गिरवी रखी गई थी। गंगा सहाय के पुत्र बिहारी ने राम अवतार वादी के वाद मित्र के रूप में इस भूमि के मोचन के लिए, जो प्रतिवादी हैं, बलबीर और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राम अवतार नाबालिग था। प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयानों में आरोप लगाया कि राम, अवतार वादी नाबालिग नहीं था और इसलिए मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। राम अवतार वादी ने 24 अगस्त, 1971 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 12 के तहत एक आवेदन दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुकदमा दायर किए जाने के समय वह नाबालिग था और उसकी जन्म तिथि 5 मई, 1953 थी और मुकदमा लंबित रहने के दौरान वह नाबालिग हो गया था और इसलिए, यह प्रार्थना की गई थी कि उसके वाद मित्र श्री बिहारी को आरोपमुक्त किया जाए और उसे अपने नाम पर मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए और उसे शिकायत में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई थी। पक्षकारों की दलीलों पर, निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दे तैयार किए गए थेः

> (1) क्या राम अवतार वादी मुकदमे की स्थापना में बड़ा था? यदि ऐसा है तो इसका क्या असर होगा?
>
> (2) राहत।
>
> पक्षकारों के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, अधीनस्थ न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वादी राम अवतार वाद की स्थापना की तारीख को नाबालिग नहीं था और इसलिए, उन्होंने 1 जनवरी, 1973 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 12 के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया। पीड़ित महसूस करते हुए, राम अवतार वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश के उस आदेश को दरकिनार करने के लिए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(3) वास्तविक तिथि नोटिस प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आज के लिए पंजीकृत डाक (पावती देय) द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है और उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाती है।

(4) संहिता के आदेश 32 नियम 12 (1) और 12 (2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक नाबालिग, बहुमत प्राप्त करने पर, यह चुन लेगा कि क्या वह वाद या आवेदन के साथ आगे बढ़ेगा और यदि वह वाद या आवेदन के साथ आगे बढ़ने का चुनाव करता है, तो वह अगले मित्र को निर्वहन करने के आदेश के लिए और अपने स्वयं के अधिकार में आगे बढ़ने की अनुमति के लिए आवेदन करेगा।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील श्री हरि मित्तल ने तर्क दिया कि निचली अदालत का यह निर्णय कि वादी वाद की स्थापना की तारीख को नाबालिग नहीं था, गलत है और इसे अलग रखा जा सकता है और यह कि भले ही वादी वाद की स्थापना की तारीख को नाबालिग नहीं था, उसे वाद में संशोधन करने की अनुमति

दी जानी चाहिए। कृष्ण कुमार ए डब्ल्यू 1 हेडमास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, दोहार कलां ने स्कूल के रिकॉर्ड और 'ए' चिह्नित प्रवेश पत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने राम अवतार याचिकाकर्ता की उम्र से संबंधित प्रवेश रजिस्टरों, प्रदर्शनी पीए, पीबी और पीसी की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं। इन प्रविष्टियों के अनुसार, राम अवतार याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 5 मई, 1953 है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि एक लड़के की जन्म तिथि के संबंध में एक सरकारी स्कूल के स्कूल रजिस्टरों में प्रविष्टियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य हैं, क्योंकि ये एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई प्रविष्टियां हैं। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि राम अवतार याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 5 मई, 1953 थी। मान लीजिए, इस भूमि से संबंधित पक्षों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। विभिन्न अधिकारियों के आदेशों की प्रतियों में, जो पीजी, पीएच, पीएफ, पीआई और पीजे हैं, राम अवतार, याचिकाकर्ता को 1969,1970 और यहां तक कि वर्ष 1971 के दौरान उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों द्वारा नाबालिग के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रवेश उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी हैं और पी. डब्ल्यू. 1 के प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार के बयान और ऊपर चर्चा किए गए स्कूल रिकॉर्ड में प्रविष्टियों का समर्थन करते हैं।

(6) बुद्ध राम, पी. डब्ल्यू. 2, राम अवतार याचिकाकर्ता के स्वाभाविक पिता हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता राम अवतार को श्रीमती कलावती ने बेटे के रूप में गोद लिया था और वह उसके साथ रहता है। बुध राम ने 16 दिसंबर, 1972 को दर्ज अपने बयान में कहा कि याचिकाकर्ता राम अवतार की आयु लगभग 19 वर्ष थी और वह मुकदमा दायर होने के समय नाबालिग था। इस गवाह ने उसे स्कूल में भर्ती कराया और 'ए' चिह्नित फॉर्म पर उसके अंगूठे पर निशान था। वह एक अनपढ़ व्यक्ति हैं। अपनी जिरह में, वह याचिकाकर्ता राम अवतार की सटीक, जन्म तिथि या जन्म वर्ष नहीं बता सके। किसी समय, उन्होंने याचिकाकर्ता/वादी की आयु 21 वर्ष या उससे भी अधिक बताई। ऐसा प्रतीत होता है कि जिरह के दौरान, वह अनपढ़ होने के कारण भ्रमित था और याचिकाकर्ता राम अवतार की जन्म तिथि नहीं बता सका। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता राम अवतार को 3 नवंबर, 1969,10 फरवरी, 1970,10 अप्रैल, 1970; 27.1970 जनवरी और 2 मई, 1971 को क्रमशः पीजी, पीएच, पीएफ, पीआई और पीजे प्रतियों में नाबालिग होने के लिए स्वीकार किया। बुध राम, पीडब्लू 2 का बयान मुकदमा दायर होने के लगभग दो साल बाद दर्ज किया गया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने इस गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में दी गई गलत उम्र के बारे में बहुत अधिक जोर दिया जो एक अनपढ़ ग्रामीण है। अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा इस गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए गए हैं। इन सभी कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि वह वाद की स्थापना की तारीख पर नाबालिग था।

(7) इस मुद्दे को साबित करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों पर थी कि याचिकाकर्ता मुकदमे की स्थापना की तारीख पर वयस्क था। प्रतिवादी में से कोई भी अपने इस आरोप का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में नहीं गया कि याचिकाकर्ता मुकदमा शुरू होने की तारीख को नाबालिग था। उन्होंने प्रदर्शन डी4 पर भरोसा किया, जो कि वादी को लिखित बयान की एक प्रति है, जिसकी एक प्रति 'डी ए' चिह्नित है, जिसमें वादी का बयान 8 अप्रैल, 1970 को दर्ज किया गया था और उसने बयान में उम्र 21 वर्ष के रूप में दी थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह आयु उन्होंने अपने कथन में नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, आयु और व्यवसाय को देते समय दी थी। उम्र के बारे में यह बयान उनके द्वारा शपथ पर नहीं दिया गया था और इसलिए इसे सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(8) इसके बाद, प्रदर्शनी डी 6 पर निर्भरता रखी गई, जिससे पता चलता है कि बुध राम की पत्नी ने 19 मार्च, 1951 को एक बेटे को जन्म दिया था। फाइल पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह जन्म प्रविष्टि याचिकाकर्ता से संबंधित है। प्रदर्शनी डी 5 में बच्चे का नाम नहीं दिया गया है। बुद्ध राम ने गवाही दी कि उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह महीना या उनकी मृत्यु का वर्ष नहीं बता सके। इस मुद्दे की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर है और वे इसका निर्वहन करने में विफल रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता वाद की स्थापना की तारीख को नाबालिग था और अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय सही नहीं है और इसे उलट दिया जाता है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री हरि मित्तल ने तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादियों के आरोपों को स्वीकार किया जाए कि राम अवतार वाद की स्थापना में नाबालिग नहीं था, बिहारी की ओर से एक वास्तविक गलती थी जिसने उसके अगले मित्र के रूप में कार्य किया और इसलिए, संहिता के आदेश 32 नियम 3 के तहत, इस गलती को ठीक किया जा सकता है और याचिकाकर्ता राम अवतार को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने वाल मोहम्मद खान बनाम इशाक अली खान और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था, "जहां एक वादी के नाम पर उसकी मां द्वारा अभिभावक और अगले दोस्त के रूप में कार्य करते हुए और उसे नाबालिग बताते हुए मुकदमा दायर किया गया है, जबकि वास्तव में वह उम्र का था और मुकदमा उसके द्वारा अधिकृत किया गया है, और उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमे को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मूल रूप से दायर की गई शिकायत में उसे उसकी मां के संरक्षण में नाबालिग के रूप में वर्णित किया गया था। इसके रूप में दोष को ठीक किया जाना चाहिए यदि यह एक वास्तविक गलती के कारण है "।

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने षण्मुगा चेट्टी बनाम सी. के. नारायण अय्यर और अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 1 नियम 10 एक ऐसे मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त है जहां एक मेजर को गलत तरीके से नाबालिग माना जाता है और उसके अगले दोस्त द्वारा उसकी ओर से मुकदमा दायर किया जाता है। इस प्रकार के मामले में अपनाने की उचित प्रक्रिया वाद को वापस करना है ताकि इसे आवश्यक संशोधन करने के बाद प्रस्तुत किया जा सके। नारायण चंद्र दास बनाम दुलाल चंद्र दत्ता में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक प्रमुख वादी एक प्रामाणिक गलती के माध्यम से होता है जिसे नाबालिग के रूप में वर्णित किया जाता है और दूसरे द्वारा अगले मित्र के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है और निचली अपीलीय अदालत ने अपील के ज्ञापन को संशोधित करने की अनुमति दी है, तो न्यायालय का आदेश पूरी तरह से सही है। दुलाल चंद्र मजूमदार और अन्य बनाम उमेश चंद्र मजूमदार में भी यही कानून बनाया गया था। इसलिए, कानूनी स्थिति यह है कि जब किसी वादी के नाम पर एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें उसे एक नाबालिग के रूप में वर्णित किया गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक प्रामाणिक गलती के माध्यम से उसके अगले दोस्त के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि वास्तव में वह एक बड़ा था, मुकदमा की स्थापना के समय, तब मुकदमा तकनीकी याचिका पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादी मुकदमा की स्थापना की तारीख पर बड़ा था और वादी को संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(10) तत्काल मामले में, यह स्थापित किया जाता है कि वादी वाद की स्थापना की तारीख पर नाबालिग था। भले ही यह माना जाए कि वह एक मेजर था, गलती प्रामाणिक थी और उसके अगले दोस्त ने

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्रामाणिक गलती के तहत भूमि के मोचन के लिए मुकदमा दायर किया कि वादी नाबालिग था। इसलिए, इस पुनरीक्षण याचिका को सफल होना चाहिए। नतीजतन, इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और राम अवतार याचिकाकर्ता/वादी द्वारा संहिता के आदेश 32 नियम 12 के तहत किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और उसे अपने नाम पर मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है और उसके अगले दोस्त बिहारी को आरोपमुक्त कर दिया जाता है। शिकायत में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए जा सकते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एच एस बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा